अमर उजाला

उत्तर प्रदेश बजट 2023-24

यूपी की उड़ान

बुनियादी ढांचा। उद्योग। बिजली

औद्योगिक निर्माण संकुल

पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनेगा। इनमें 4 पूर्वांचल और 2 संकुल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे।

3000 करोड़ राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए की व्यवस्था

401 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए प्रस्तावित

भारी-मध्यम उद्योगों को तरजीह

अवस्थापना सुविधाओं और औद्योगिक गलियारों का होगा विकास

2588 करोड़ रुपये राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण के लिए

2538 करोड़ प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण व नए कार्यों के लिए की व्यवस्था

1000 करोड़ धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए प्रस्तावित

500 करोड़ रुपये नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास पर खर्च होंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के बजट में भारी और मध्यम उद्योगों के लिए 20586 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दो लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से डिफेंस कॉरिडोर के झांसी और चित्रकूट नोड तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे औद्योगिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी।

20586 करोड़ रुपये भारी एवं मध्यम उद्यम मद में की गई व्यवस्था

भारी और मध्यम उद्योग के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 9826.95 करोड़ रुपये पूंजीगत मद यानी नई संपत्तियों के सृजन पर खर्च होंगे। इसमें दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, उपभोक्ता उद्योगों व अन्य उद्योगों के मद में बजट की व्यवस्था की गई है। नए औद्योगिक विकास व निवेश के लिए अवसर खोलने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और यातायात का दबाव कम करने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह से चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्टेट डाटा सेंटर को विकसित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उप्र. सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, उप्र. स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड और स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड की शासकीय देयताओं के भुगतान के लिए 878.18 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

बाराबंकी व रायबरेली की स्पिनिंग कंपनियों के बकाए के लिए 287.95 करोड़

उप्र. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड की रायबरेली, मऊनाथ भंजन और बाराबंकी इकाइयों पर बकाया ऋण और अंशपूंजी मद में अनुदान के लिए 287.95 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ व हरदोई सीमा पर टेक्सटाइल पार्क

लखनऊ और हरदोई सीमा पर कृषि विभाग की चिह्नित 1000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इलेस्ट्रेशन सुरजीत दोषी

एमएसएमई और वस्त्र नीति के लिए 250 करोड़

एमएसएमई क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार पैदा होने की स्थिति को देखते हुए एमएसएमई नीति-2022 को लागू करने के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है। उप्र. सेवा क्षेत्र नीति-2022 को लागू करने के लिए एक करोड़ का बजट प्रावधान है। उप्र. वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

युवाओं के लिए 17 पायलट वर्कशॉप

अमरोहा, बागपत, अमेठी, संभल, शामली, हापुड़ के अलावा वाराणसी व चंदौली में जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र और उद्यमिता विकास केंद्र के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 5.55 करोड़ दिए गए हैं। युवाओं के तकनीकी उन्नयन के लिए 17 राजकीय पायलट वर्कशॉप के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अलीगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर, राजकीय चीनी पात्र विकास केंद्र, झांसी, कृषि यंत्र संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी के पुनर्निर्माण या सुदृढ़ीकरण पर यह राशि खर्च होगी।

बुनकरों के बिजली बिल की भरपाई करेगी सरकार

बजट में निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए निवेशकों को आर्थिक सहायता देने के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट में बुनकरों का खास ध्यान रखा गया है। इनके बिजली बिल की भरपाई के लिए 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नए औद्योगिक आस्थानों के लिए 75 करोड़ और उप्र. निर्यात अवस्थापना विकास योजना के लिए 10 करोड़ का बजट दिया गया है।

2.50 करोड़ नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के लिए। यहां वैदिक विज्ञान और तप स्थल अध्ययन केंद्र की स्थापना भी होगी